सारणी 2 : हिमाचल प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में किया गया निवेश (1951-2012)

योजनाएं	कुल निवेश (लाख रुपये में)	विद्युत क्षेत्र में निवेश (लाख रुपये में)	विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश का प्रतिशत
पहली योजना (1951-56)	527.25	21.59	4.09
दूसरी योजना (1956-61)	1602.6	150.69	9.40
तीसरी योजना (1961-66)	3384.47	240.14	7.10
वर्षीय योजना (1966-67)	946.05	295.04	31.10
वर्षीय योजना (1967-68)	1443.94	395.52	27.39
वर्षीय योजना (1968-69)	1595.19	415.75	26.06
चौथी योजना (1968-74)	11342.97	2450.03	21.60
पांचवीं योजना (1974-78)	16148.48	4053.89	25.10
वर्षीय योजना (1978-79)	6810.17	1248.54	18.33
वर्षीय योजना (1979-80)	7945.36	1550	19.51
छठी योजना (1980-85)	65566	17924.95	27.34
सातवीं योजना (1985-90)	132475.75	34747.61	26.23
वर्षीय योजना (1990-91)	37762.93	6721.58	17.80
वर्षीय योजना (1991-92)	40740	5344.34	13.12
आठवीं योजना (1992-97)	349905	67692.79	19.35
नौवीं योजना (1997-2002)	789672	126623	16.03
दसवीं योजना (2002-2007)	-	62243.62	-
ग्यारहवीं योजना (2007-12)	-	68924	-
बारहवीं योजना (2012-17)	-	82972	-

स्रोत : हिमाचल सरकार की वार्षिक मसौदा योजना (2003-04) व केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की 12वीं जल विकास योजना (2012-17) से संकलित।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड अपने गठन 1971 से ही राज्य के भीतर हो रहे विद्युत क्षमता के विकास, उसके वितरण और ट्रांसमिशन के लिए कार्य कर रहा है और सफल भी रहा है

में अनूठा है क्योंकि राज्य की लगभग 91.8 फीसदी जनसंख्या 350 से 4900 मी. की ऊँचाई पर बसे गांवों में रहती है। दुनिया का सबसे अधिक ऊँचाई पर बना हुआ पॉवर हाउस 'रोंगटांग' हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इतनी अधिक ऊँचाई पर विद्युत उत्पन्न करना और मुहैया करवाना अपने आप में एक उपलब्धि है। यह सब राज्य में मौजूद जल संसाधनों के कारण सम्भव हो पाया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश ने जलविद्युत निर्माण की चुनौती को स्वीकार तो किया है परन्तु इसका निर्माण व संचालन सदैव राज्य के भौतिक और जैविक पर्यावरण में परिवर्तन से सम्बन्धित रहा है। अधिकांश जलविद्युत परियोजनाओं ने पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को अनदेखा किया है और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया है। नकारात्मक प्रभावों में वनस्पति और कृषि भूमि का विनाश, नदी के प्रवाह और प्रतिरूप में बदलाव, अनैच्छिक पुनर्वास, स्वास्थ्य समस्यायें, नदी की निचली घाटी में सूखे या पानी के कम प्रवाह की समस्या तो कभी बाढ़ की समस्यायें मुख्य रही हैं। पोंग और भाखड़ा परियोजनाओं से विस्थापित लोगों को अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है, हालांकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जलविद्युत परियोजनाओं में अलग से धनराशि रखी जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि इस धनराशि का प्रयोग जलविद्युत शक्ति के विकास से हुए पर्यावरणीय विनाश की बजाय अन्य दूसरे कार्यों जैसे कि वहां के कर्मचारियों को वेतन आदि देने में खर्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जलविद्युत विकास से होने वाला पर्यावरणीय ह्रास ज्यों का त्यों बना रहता है जो कि राज्य के पर्यावरणीय संतुलन के लिए ठीक नहीं है। अतः राज्य सरकार का ध्यान इस ओर अपेक्षित है ताकि जलविद्युत विकास के साथ-साथ राज्य में पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखा जा सके व भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण से वंचित न होना पड़े।

संपर्क करें :
डॉ. ओमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र-136 119
[ई-मेल:ovshome@yahoo.com, ovshome@gmail.com]

प्रकृति का उपहार

नदियों की कल-कल में, झरनों की झर-झर में,
सागर की लहरों में, वर्षा के पहरों में,
हिम के पिघलने में, नलकूपों के चलने में,
सावन की पुरवाई में, काली घटा की तन्हाई में,
सबमें छिपा है, प्रकृति का अनमोल उपहार,
जो है हमारे जीवन का आधार।
बिना जल, जीवन की कल्पना असंभव है,
इसकी महत्ता शब्दों में बयां करना न संभव है,
पेड़-पौधे, पशु-पक्षी सबका इससे नाता है,
बिना जल के कोई भी न रह पाता है,
मानव की प्रकृति का है परिचायक,
कृषि व उद्योगों में है यह सहायक।
इस अनमोल द्रव की महत्ता समझकर,
इसको न बर्बाद कीजिए,
जितनी जरूरत हो, उतना व्यय करके,
वर्षा के जल का संरक्षण कीजिए।
धरा को तुम वृक्षों से सजाकर,
बादलों से इस अमृत का निर्माण कीजिए,
सिद्धान्तों में कहने से कुछ नहीं होता,
कर्मों में अपने तुम प्रयोग कीजिए।

संपर्क करें:
कु. शशि
पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह वर्मा
ग्राम-पचघरा, डाकघर-खरवहिया नं. 1,
जिला-लखीमपुर खीरी- 262 723
(उ.प्र.)
मो. : 09889041666